MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, we will consider it after Rajasthan has been finished.

I. THE BUDGET (RAJASTHAN) 1980-81—General Discussion.

II. THE RAJASTHAN APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL 1980.

III. THE RAJASTHAN APPROPRIATION BILL, 1980.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Rajasthan for the services of a part of the financial year 1980-81, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I also beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Rajasthan for the services of the financial year 1979-80, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I am not going to make any speech. I reserve my right to reply to the points which will be made. I hope the House will agree to the proposals that have been made.

The questions were proposed.

श्री हरीशंकर भाभड़ा (राजस्थान) : श्रीमन्, इसके पहले कि राजस्थान के बजट के सम्बन्ध में कुछ कहा जाए, मैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मान्यवर, राजस्थान एक सीमावर्ती प्रान्त है जिसके नौ जिले रेगिस्तानी हैं, आठ जिले पहाड़ी हैं और नौ जिले एसे हैं कि जो समतल मैदान में है। राजस्थान के कुल क्षेत्र में से 55 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जो केवल रेगिस्तानी हिस्सा है। राजस्थान में सारे देश की आबादी का 4.7 प्रतिशत भाग है, क्षेत्रफल कुल देश का 11 प्रतिशत है। लेकिन राजस्थान में जहां तक खनिज का सवाल है, अतुल भंडार खनिज का राजस्थान में है, जो आठ सौ करोड़ रुपए से एक हजार करोड़ रुपए तक हो सकता है। राजस्थान में पशुधन अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम नहीं है और ऊन का उत्पादन तो राजस्थान में 40 प्रतिशत सारे देश का होता है।

जहां तक राजस्थान में गरीबी की रेखा के नीचे लोगों की संख्या है, जब सारे भारतवर्ष में औसत 43 प्रतिशत है, राजस्थान में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की औसत 56.3 है, जिसमें से 81 प्रतिशत खेतिहर मजदूर और 50 प्रतिशत किसान हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। जहां सारे देश की औसत वार्षिक आय रु० 850 है, राजस्थान में वार्षिक आय प्रति व्यक्ति रु० 769 है।

The Vice-Chairman, (Shri Sawai Singh Sisodia), *in the Chair.*

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, राजस्थान जम्मू-काश्मीर को छोड़ कर के सब से नीचे है। केवल 19 प्रतिशत लोग राजस्थान में शिक्षित हैं।

जहां तक सड़कों के बनाने का सवाल है, जबकि सारे देश का औसत 37 किलोमीटर है, राजस्थान में 14.6 किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बनी हुई हैं।

जहां तक खाद के उपयोग का सवाल है, जबकि सारे देश की औसत 17.1 किलोग्राम प्रति हैक्टर है, वहां राजस्थान में केवल 4.9 किलोग्राम प्रति हैक्टर है।

यह है राजस्थान का भौगोलिक नक्शा लेकिन इसके बावजूद, जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा, यह जो बजट हमारे सामने

[श्री हरीशंकर भाभड़ा]

आया है यह अन्तिम बजट नहीं है, यह अंतरिम बजट है और आने वाली सरकार इस में परिवर्तन कर सकती है और असली बजट तब आएगा, जब नया करारोपण किया जाएगा। जब यह मालूम होगा नयी सरकार कौन से कर लगाने जा रही है तब असली बजट की सूरत हमारे सामने आएगी। इसलिए इस समय बजट में जो आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों के बारे में कुछ भी कहना समयोचित नहीं होगा क्योंकि वित्त मंत्री महोदय पहले से ही इस का जबाब लोक सभा में दे चुके हैं कि यह अन्तरिम बजट है जिस में परिवर्तन किया जा सकता है और जो भी नयी सरकार चुन कर आएगी वह परिवर्तन लाएगी। लेकिन मान्यवर, एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, पिछली सरकार, जिसको केन्द्र सरकार ने बरखास्त किया है, उस सरकार के जो कार्य हैं उन कार्यों के बारे में थोड़ा सा वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा ताकि जिस स्पिरिट से वह सरकार काम कर रही थी उसी स्पिरिट को मेनटेन करने के लिए, उसे चालू रखने के लिए बजट में प्रावधान किये जाएं। मान्यवर, राजस्थान में जनता सरकार ने न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व के अन्दर अपनी अंत्योदय योजना को लेकर यश प्राप्त किया है और इस सम्बन्ध में मैं एक राय कोट करना चाहूंगा, एक तो एकानामिक टाइम्स लंदन, ता० मई 21, 1978 की और एक है वरल्ड बैंक के चेयरमैन मेकेनमारा की। ये दोनों राय इसलिए मैं बताना चाहूंगा क्योंकि अन्यथा इसको पोलिटिकलाइज किया जा सकता है व यह कहा जा सकता है कि राजनतिक दृष्टि से भिन्न राय हो सकती हैं। एक तटस्थ और बाहरी देश की राय क्या है, यह मैं बताना चाहता हूं।

The Economist, London, says:

"Rajasthan is the only State in India run by the Janata Party, which also runs the Central Government...where the local administration has actually got on with governing and, in particular, with doing something about rural poverty. Voters acknowledged these efforts this week by giving Janata its first by-election victory for some time with two-to-one margin over Mrs. Gandhi's candidate in a poll for the State Assembly. The poverty programme which Rajasthan has adopted is known as the Antyodaya movement. It seeks to identify the five poorest families in each village and make them self sufficient. Once they have been rehabilitated, the focus shifts to the next five poorest families, in this wage the plan rolls on to help those most in need."

इसके आलावा मिस्टर राबर्ट मेक मारा ने जो कहा है, टाइम्स आफ इंडिया, न्यू दिल्ली अक्तूबर 4, 1978 में छपा है :

"Mr. Robert Mcnamara, World Bank Chief, said today that his organisation and the Ford Foundation would consider how they could assist people's welfare schemes such as the Rajasthan Government's Antyodaya programme. The World Bank Chief said he was happy to see these people helping themselves with the assistance they had received. The Antyodaya programme had given opportunity to the people to increase their income through their labour."

मान्यवर, इस अंत्योदय प्रोग्राम में राजस्थान की कुल आबादी जो 2 करोड़ से कुछ ज्यादा है उस में से 2 लाख 10 हजार फैमिलीज–यदि हम एक फैमिली में 5 व्यक्ति गिनेंगे—तो लगभग 10 लाख से ऊपर लोगो को रिहेबिलिटेट किया है। तो आज 2 लाख 10 हजार फैमिलीज राजस्थान के अन्दर अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपनी कमाई स्वयं कर रही हैं। उन को हर प्रकार की सहायता दी गई है। इसके अलावा पिछली सरकार ने फूड फार वर्क के अन्दर जो काम किया था, कामके बदले अनाज का वह सारी स्टेट्स से पहले और सबसे अधिक किया है। 2 लाख 68 हजार टन गेहूं का कार्य राजस्थान

में किया गया। 35 करोड़ रु० का अनाज बांटा गया और साढ़े 5 करोड़ रु० नकद ग्राम पंचायतों को मदद दी गई और 15 करोड़ रु० जनता ने लगा कर कुल 55 करोड़ रुपये का काम, अनाज के बदले काम में खर्च हुआ है। यह अपने आप में रिकार्ड है। मैं जो फिगर्स दे रहा हूं। वे अपने आप में रिकार्ड है, मैंने स्वयं गांवों में देखा है, पहली बार 30 वर्ष में ग्राम पंचायतों ने इस बात को अनुभव किया कि हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज है जब कि एक सरपंच और ग्राम पंचायत को इतना अधिकार है कि वह हजारों की तादाद में, बिना किसी गवर्नमेंट मशीनरी की सेंक्शन के और बिना किसी बाधा के, रुपया अपने आप खर्च कर सकता है। जिस रास्ते से किसी गांव में एक आदमी नहीं गुजर सकता था उस रास्ते को गांव वालों ने इतना चौड़ा बना दिया कि आप एम्बेसेडर ले कर घूम सकते हैं। राजस्थान के अनेक गांवों में यह काम हुआ है। इस प्रकार से 40 हजार विकलांगों को घर बैठे पेंशन दे कर राजस्थान की भूतपूर्व सरकार ने उनको भूखों मरने से बचा लिया है।

7 P.M.

मैं इन कामों को इस लिए बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार यह काम इस लिए कर पायी कि उस ने ग्राम पंचायतों का सहयोग प्राप्त किया और ग्राम पंचायतों ने काफी सहयोग दिया। कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ ग्राम पंचयातों के सरपंच खा गये। इतने बड़े काम में हो सकता है कि किसी ने कुछ खाया भी हो। मैं सही बात कहने से हिचकूंगा नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : जल्दी करिए।

श्री हरीशंकर भाभड़ा : जल्दी नहीं करूंगा : I have said that I will take my full time. We are ready to sit up to 9 o'clock. So, I have submitted before the Deputy Chairman and he has agreed and we will take the same amount of time as Punjab has taken.

यह जो स्पिरिट थी ग्राम पंचायतों को साथ में ले कर लोकल लोगों की मदद से काम करने की इस स्पिरिट को बरकरार रखा जाये, यह मेरा निवदन है क्योंकि अभी जो केयरटेकर गवर्नमेंट बनी है उसने सब से पहला काम यह किया है कि काम के बदले अनाज का काम जो पहले पंचायतों के मार्फत होता था, अकाल राहत का काम जो पंचायतों की मार्फत होता था उस को उन्होंने बन्द कर दिया है और शायद उसके पीछे मोटिव वही है कि वे कुछ पैसा बनाना चाहते हैं। ग्राम पंचायतों में सभी तरह के लोग हैं। सभी ग्राम पंचायतें हमारी नहीं हैं, आप के लोग भी बैठे हुए हैं। कांग्रेस (आई) के सरपंच भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने पसा भी कमाया है, सब तरह के लोग हैं। लेकिन कुल मिला कर राजस्थान में एक वातावरण बना है, राजस्थान में कुछ काम हुआ है और राजस्थान की जनता अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रयत्नशील हुई है। लोगों को इस बात से राहत मिली है। गांव की सब से कमजोर पांच ही फैमिलीज को मदद मिली है इतना ही क्यों ? पांच फेमिलीज को तो मदद मिली है यह बड़ी बात है। बड़ी बातें करने से, गरीबी हटाओ कहने से क्या होता है ? यदि पांच आदमियों की गरीबी हटती है तो बाकी पांच में इस बात का विश्वास पैदा होता है कि कल हमारा नम्बर भी आ सकता है। तो यह स्पिरिट मेन्टन की जानी चाहिए, यह मेरा पहला निवेदन है।

अब मैं सरकार को कुछ ऐसे मुद्दों पर सजेशन्स देना चाहूंगा जो राजस्थान

[श्री हरीशंकर भाभड़ा]

के बर्निंग प्राबलम्स हैं। मैं चाहूंगा कि जहां तक केन्द्रीय सरकार की एसिस्टेंस का सम्बन्ध है उसको देने में राजस्थान के प्रति जो अब तक सौतेला व्यवहार होता रहा है वह समाप्त किया जाये। राजस्थान बैकवर्ड है, योजना की दृष्टि से राजस्थान बैकवर्ड क्षेत्र कहा जा सकता है, उसमें पूरा राजस्थान आता है। इस क्षेत्रीय असन्तुलन को हमें समाप्त करना पड़ेगा। म इस स्थिति को लम्बे समय तक नहीं चला सकते। राजस्थान में कितनी खनिज सम्पदा है, कितने मवेशी हैं, कितना प्रोडक्शन पोटेंशियल है, इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड रिसर्च की रिपोर्ट 1961 की ओर आकृष्ट करूंगा जिस में उन्होंने वहां के औद्योगिक विकास की क्षमता बताई है। उन क्षमताओं के उपयोग के लिए प्रापर इन्फ्रा स्ट्रक्चर राजस्थान में बने इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री ध्यान अवश्य दें।

राजस्थान में सब से बड़ी समस्या पावर की आ रही है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राजस्थान को थीन, वारासियूल और सलाल हाइडल स्कीम जो बन रही है उन में कोई हिस्सा नहीं है जब कि राजस्थान को भी इस में पावर मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस बात पर खास तौर से गौर करेंगे।

दूसरे राजस्थान में जो पावर शार्टेज है उस को मीट करने के लिए एक प्रपोजल केन्द्रीय सरकार के पास पलाना में थरमल पावर स्टेशन बनाने के लिए दिया गया है, जिस की इन्सटाल्ड कैपेसिटी 120 मेगावाट है। इस को जल्द से जल्द बना दिया जाये तो कम से कम उत्तर और पश्चिम राजस्थान के लिए इस सारी पावर को सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि पश्चिम राजस्थान, केनाल का कमान्ड एरिया भी है जो अभी पावर जनरेशन के टेल एन्ड पर है। पलाना थरमल पावर स्टेशन चालू हो जाएगा तो पश्चिम राजस्थान वालों को बहुत सुविधा होगी और इस से उन को डेवलप करने का काफी मौका मिलेगा। इस संबंध में सेन्ट्रल असिस्टेंस के लिये जो प्वाइंट्स हैं उन्हें मंत्री महोदय अगर नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। पहला प्वांइट है :

(i) Special additional allocation of funds for execution of the generation projects in Rajasthan over and above what is admissible in context to the total size of the Annual Plan for the State of Rajasthan.

(ii) Emphasising the need and urgency for establishing a pumped storage scheme near Kota between Rana Pratap Sagar and Jawahar Sagar hydel power stations.

(iii) Pressing for admitting the entitlement of Rajasthan in the new hydel schemes such as Thein hydel scheme, Mukerian hydel scheme and Anandpur Sahib where the storage waters in which Rajasthan has shared is proposed to be utilised for developing hydro power.

(iv) For expediting the investment sanction for extension of Kota Thermal project.

इनके लिये सभी आप ध्यान देंगे, यह मेरा निवेदन है। जहां तक आर० ए० पी० राजस्थान अटोमिक पावर कोटा को अगर कोयला की सप्लाई बराबर मिलती रहे, तो उसके चालू रहने से राजस्थान की जनता को काफी राहत मिल सक्ती है। पिछले दिनों आर० ए० पी० बंद थी वह चालू हो

गई है अगर वह इसी तरह चालू रहे तो तावर की समस्या राजस्थान में हल हो सकती है। इसके बाद मेरा दूसरा महत्वपूर्ण प्वांइट यह है...

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : यह तो तीसरा है।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : यह तो सजेशन के तौर पर दूसरा है। मैं तो एक-एक लेकर बोल रहा हूं।

राजस्थान केनाल जो कि विश्व की सबसे बड़ी नहर है जिसका अभी प्रथम चरण समाप्त हुआ है। इसमें 179 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर है और लगभग तीन हजार वितरक नहरे हैं जो कि सिंचाई करने वाली हैं, वे अभी बननी हैं। यह काम पिछले दो सालों में स्पीड-अप हुआ था, जो 20 साल से पैंडिंग पड़ा था, लेकिन सीमेंट की कमी के कारण फिर से यह काम रुक गया है। वहां पर सीमेंट की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिये ताकि राजस्थान केनाल के काम को अतिशीघ्र किया जा सके। इसका जो दूसरा फेज है वह सबसे बड़ा फेज है। कुल मिला कर राजस्थान की मुख्य नहर जो होगी वह 445 किलोमीटर की होगी और जो वितरक नहीं बनेंगी वह 6500 किलोमीटर होंगी। इस काम को पूरा करने के लिये मुझे इस बात की खुशी है कि लोक सभा में वित्त मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि जितना एक साल में खर्चा होगा उतना खर्च करने का प्रोविजन वह करेंगे। यह बहुत खुशी की बात है और राजस्थान की जनता भी इससे खुश होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह काम नहीं हो रहा है और इसका कारण यह है कि सीमेंट नहीं मिल रहा है इसलिये सीमेंट की व्यवस्था की जाए ताकि राजस्थान केनाल का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके।

SHRI ERA SEZHIYAN: Sir, I appeal to the House and also to the Leader of the House that we take up the discussion on the Budgets of Tamil Nadu, U.P. tomorrow after 2 o'clock. We assure our full cooperation. We can dispose of other business, and sharp at 2 o'clock we can take up the Budget discussion on Tamil Nadu and UP. I hope this will be in order.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I agree with him. Today we can finish Rajasthan Budget, and tomorrow up to 2 o'clock Calling Attention and whatever other business it is there; that would be over by 2 o'clock. And if it is not over, at 2 o'clock, Sir, we shall take up the Tamil Nadu and U.P. Budgets, and after these, if there is any left-over business, that can be taken up after that. I would request Mr. Sezhiyan and other Opposition Members to co-operate. From the Government's side we are prepared to accept this suggestion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): So the suggestion is that from 2 o'clock tomorrow we will take up the Tamil Nadu and U.P. Budgets.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: There is also one more business—an Ordinance to be replaced by the Act.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): It will also come up.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: After that, we can have Special Mentions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): The suggestion is before the House that from 2 o'clock tomorrow we will take up the Tamil Nadu and U.P. Budgets...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: And one Ordinance. Special Mentions can be there after that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): After these three items are over, if it is the wish of the House, we can tak up the other business.

SOME HON. MEMBERS: Yes, yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): So, it is the consensus of the House. Now, we go to the remaining discussion on Rajasthan budget. We shall take up the budgets of Tamil Nadu and Uttar Pradesh and the Ordinance tomorrow at 2 o'clock.

श्री हरीशंकर भाभड़ा : मान्यवर, इस राजस्थान नहर से करीब 28 लाख एकड़ कृषि भूमि में सिंचाई होगी जिसमें 31 लाख टन कृषि सामग्री होने की सम्भावना है और इसके फस्ट फेज में ही 15 मिलियन टन कृषि सामग्री पैदा होने की आशा है । परन्तु इसके ट्रांसपोरटेशन के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो रोड्स चाहिए, जो रेलवे लाइनें चाहिएं, उनकी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है । इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कैनाल एरिया की अभिवृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी वे व्यवस्था करें।

इसके अलावा मेरा निवेदन यह भी है कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पीने के पानी की बहुत भारी कमी है । लगभग 90 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है । खास तौर से नागौर, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्रों में पीने का पानी नहीं है । मेरा यह निवेदन है कि इस पीने के पानी की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए । इन क्षेत्रों को ईरीगेशन के लिए राजस्थान कैनाल से पानी नहीं मिल सकता है । लेकिन कम से कम पीने के लिए तो पानी इस कैनाल से दिया जा सकता है । अभी राजस्थान कैनाल से केवल पांच सौ क्वीजक पानी पीने के लिए सुरक्षित किया गया है जो कि गंगानगर, बिकानेर और जैसलमेर के लिए ही अपर्याप्त है । इसलिए मेरा निवेदन है कि नागौर, बाड़मेर और जोधपुर के लिए भी पीने का पानी इस नहर से मिले, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए । इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि पीने का पानी अधिक मात्रा में सुरक्षित किया जाये और इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये । मान्यवर, आप जानते हैं कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है । जो भी केन्द्रीय सहायता राजस्थान को मिलती है वह बहुत ही कम है । गाडगिल फारमूले के मुताबिक राज्यों को सहायता दी जाती है । वित्त मंत्री महोदय ने लोक सभा में कहा था कि This formula has stood the test of time.

मेरा निवेदन यह है कि कोई फारमूला कितना ही अच्छा क्यों न हो, कभी-कभी उसको समय के अनुसार बदलना पड़ता है । देश के हित के लिए, जन विकास के लिए अगर किसी फारमूले को बदलना पड़े तो उसको बदल देना चाहिए । सम्पूर्ण राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश है । अभी तक राजस्थान को गाडगिल फारमूले के मुताबिक 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता दी जाती है । मेरा कहना यह है कि इसको 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आपके 20 मिनट समाप्त हो गए हैं ।

श्री हरीशंकर भाभड़ा : जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाने का सवाल है, राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि सारे देश की पूंजी की केवल 2.2 प्रतिशत पूंजी ही राजस्थान में लगी हुई है । सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाने के लिए खाद के कारखाने, सीमेंट के कारखाने और नमक के कारखाने लगाये जा सकते हैं । यहां तक कि अशोक लेलैण्ड के कारखाने भी राजस्थान में लगाये जा सकते हैं । लेकिन इस सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं

दी गई है। राजस्थान में अंतिम बार सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी 15–20 वर्ष पहले लगाई गई थी। उसके बाद आज तक सार्वजनिक क्षेत्र में एक पैसा भी राजस्थान में नहीं लगाया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान में उद्योगों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग धंधे खोलने के लिए पूंजी लगाई जानी चाहिए और इस के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया है, राजस्थान में शिक्षा की इतनी कमी है कि केवल 19 प्रतिशत लोग ही वहां पर शिक्षित हैं, इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के विकास के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाये। इसके लिये जो 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यह अपर्याप्त है। इसको बढ़ाया जाना चाहिये। पिछले दो सालों में वहां काफी स्कूल खुले हैं। सभी ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या तीन हजार है वहां पर मिडिल स्कूल खोल दिये गये हैं और ऐसे भी गांव हैं जिनकी जनसंख्या पांच हजार है वहां पर हाई स्कूल खोल दिये गये हैं। पिछले दो सालों में वहां पर स्कूल खोलने का प्रयास किया गया है और ऐसे सभी स्थानों पर स्कूल खोले गये हैं। लेकिन उनको चलाने के लिये फर्नीचर और स्टाफ आदि के लिये धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं वित्त राज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोटा, जो कि उनके मतलब की बात है, पालिटिक्स कालेज को इंजीनियरिंग कालेज में बदलने के लिये पिछली सरकार ने प्रोविजन किया था, मैं आशा करता हूं कि वे उसको चालू रखेंगे। यह मंत्री महोदय के क्षेत्र की बात है लेकिन कह मैं रहा हूं।

इसके अलावा राजस्थान में कैटल ब्रीडिंग का काम हो सकता है, पशु धन को बनाये रखने के लिये और उनको प्रोत्साहित करने के लिये राजस्थान में डेरी उद्योग को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है और पश्चिम राजस्थान में डेरी उद्योग एक प्रामिनेन्ट पार्ट प्ले कर सकता है, यदि सरकार थोड़ी सी मदद करे।

जहां तक सप्लाई का सवाल है, राजस्थान में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नियमित रूप से होनी चाहिये। यहां पर बहुत से लोगों ने अपने-अपने राज्यों की सप्लाई को नियमित करने के लिये कहा। मेरा भी निवेदन है कि वहां पर भी पैट्रोल, डीजल, सीमेन्ट आदि आवश्यक चीजों की सप्लाई को और बढ़ाया जाना चाहिये।

अन्त में मेरा निवेदन है कि राजस्थान में पर्यटन स्थलों के सम्बन्ध में। राजस्थान में बहुत से पर्यटक केन्द्र हैं जिनके विकास की जरूरत है परन्तु इनका विकास बिना केन्द्रीय सहायता के हो नहीं सकता। इससे सरकार को काफी आमदनी होने की सम्भावना है। परन्तु वहां पर जाने के लिये साधनों का अभाव है। यहां तब कि जोधपुर में भी सिविल एरोड्रम साल भर पहले बना था, परन्तु हवाई जहाज की सर्विस नहीं है। जैसलमेर में हजारों विदेशी जाते हैं परन्तु उनको जाने के लिये वहां एक ट्रेन शाम को जाती है और कोई साधन नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर हवाई सर्विस को चालू किया जाये ताकि वहां के पर्यटन स्थलों पर जाने के लिये लोगों को सुविधा हो। इसलिये मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इसके विकास की ओर ध्यान दे। इन का विकास करने से सरकार को भी लाभ हो सकता है।

मैं समझता हूं वाइस-चेयरमैन साहब कि अब मैं आपको धन्यवाद दूं क्योंकि आपने मुझे समय दिया। जहां तक

[श्री हरीशंकर भाभड़ा]

हुआ है मैंने बहुत संक्षेप में अपनी बात कही है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय मेरी इन बातों पर ध्यान देंगे।

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ (राजस्थान) : वाइस-चेयरमैन साहब, मैं बजट का तो स्वागत करता हूं लेकिन इसके साथ ही अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि बजट में जितना प्रावधान सूखे के सिलसिले में रखा गया है, वह बहुत कम है। गवर्नर राजस्थान ने एक करोड़ का मतालबा किया है और मैं समझता हूं कि वह मतालबा वक्त के मुताबिक बिल्कुल सही था। मौजूदा अकाल में राजस्थान के 25 हजार गांव और करीब 2 करोड़ 40 हजार जनता अकाल की तकलीफ में है। हजारों लोग अपने गांव छोड़ कर दूसरे सूबों में मुनतकिल हुए हैं और हो रहे हैं। फिर भी उनको रोजगार नहीं मिलता। उनके जानवर और उनके मवेशी हजारों की तादाद में मर चुके हैं और जो जिन्दा हैं वे अनाज और चारे के अभाव में भटक रहे हैं। उनके लिये घास और चारे का इंतजाम नहीं है। बड़े-बड़े जमीदार गरीबों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हुए कर्जा देते हैं और जमीन को कौड़ियों के मूल्य में खरीद रहे हैं और व्याज की दर 50 फीसदी के करीब है। यह तमाम हालत करीब साल भर से जारी है। मगर जाने वाली सरकार ने इन चीजों की तरफ तवज्जोह नहीं दी, न राहत के काम खोले, न अावाम के लिये रोजगार और मजदूरी का बंदोबस्त किया। जो कुछ अकाल के लिये राहत के काम खोले गये थे, जाने वाली सरकार ने बन्द कर दिये और अपने जाने के आसार देख कर जो कुछ काम हुआ था उसका पेमेन्ट तक नहीं किया। गरीब मजदूरों की तीन-तीन, चार-चार महीने की मजदूरी बाकी है और रुकी हुई है। उनका पेमेंन्ट नहीं हुआ है। यह तमाम इसलिये किया गया है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ जजबात भड़के। अकाल के सिलसिले में, पीने के पानी और खेती की स्कीम के लिये ज्यादा रुपये दिये जाने चाहिये। बहुत सी स्कीमें अधूरी पड़ी हैं। अकाल के कामों में जो लगे हुए हैं उनको मजदूरी तीन किलोग्राम जो अनाज दिया जाता है बहुत नाकाफी है। जाने वाली निकम्मी सरकार ने अंत्योदय प्रोग्राम, फूड फार वर्क (काम के बदले अानाज) के प्रोग्राम चलाये थे, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं अर्ज करूं कि हमारे 20 सूत्री प्रोग्राम की नकल करते हुए ये दोनों काम शुरू किये गये और इसका शोर देश में मचाया गया। मगर दोनों प्रोग्राम खोखले साबित हुए। गांव में तीन-चार परिवारों को बैंक ऋण दिया गया। ऋणों को देने का सिलसिला जो रहा। उससे मिडिल-मैन कर्जो को हड़प कर गये और इसमें बड़ी बेइमानी हुई। जो दो-दो, तीन-तीन परिवार गांव में छांटे जाते, वे मुख्य मंत्री के ख्यालात और मिजाज के लोग होते थे। इस तरह उन्होंने हर गांव में दो-दो या चार-चार परिवार इस तरह के तैयार कर दिये जो गांव में कांग्रेस के खिलाफ सियाशी जज्बा पैदा करने की कोशिश करते थे। इसका गरीबों के उत्थान से कोई ताल्लुक नहीं था। काम के बदले अनाज योजना में बड़े घपले हुए। पंचों और सरपंचों ने जो मुख्य मंत्री के ख्यालात के थे अनाज हड़प कर लिया। गरीबों को उनका हिस्सा नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार इस सिलसिले में छानबीन करके इस साजिश का पर्दाफाश करे और बीस सूत्री कार्यक्रम को सही तौर पर लागू करने के इन्तजामात करे। मैं मिनिस्टर साहब को तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में हजारों बन्धुवा

मजदूर हैं। उनको राहत दिलाने के लिये और छुटकारा दिलाने के लिये फौरी कदम उठाये जाने चाहियें। राजस्थान में मिनिमम वेजेज एक्ट पर भी अमल नहीं हो रहा है। इस पर भी अमल करवाया जाय। मैं यह भी शिकायत करूंगा कि तालीम के लिये बजट में काफी कटौती कर दी गई है, जो मुनासिब नहीं है बल्कि इसमें इजाफा किया जाना चाहिये था। यही हालत इंडस्ट्रीज और हैल्थ के सिलसिले में है। जाने वाली सरकार डीजल और मिट्टी का तेल, पीने का पानी और बिजली गांव को नहीं दे सकी और अब उसकी हालत रोजबरोज खराब होती चली जा रही है, जिसका सुधार करने के लिये जल्दी से जल्दी तवज्जो होनी चाहिये। अफसोस की बात है कि ऐसी हालत में भी किसान की लगान का वही रेट देना पड़ता है जो पहले था। इसमें कमी होनी चाहिये। क्योंकि अकाल की वजह से वह बहुत ही तकलीफ में है। मैं सरकार की तवज्जो इस तरफ खास तौर पर दिलाउंगा कि जिला बीकानेर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों और जिला गंगानगर में राठी नस्ल की गाय मिलती है जो मुल्क भर में ज्यादा दूध देने में मशहूर है। मुतवातिर अकाल पड़ने की वजह से यह पशु धन बहुत कुछ बरबाद हो चुका है और जो बाकी बचा है उसको बचाने के लिये कारगार तरीका निकाला जाना चाहिये। मसलन उसके लिये चारे का इंतजाम किया जाये। पंजाब, हरियाणा और गंगानगर जिले से चारा लाने के लिये सबसिडी मंजूर की जानी चाहिये, ट्रकों का इंतजाम किया जाये। गवार जो बहुत जरूरी चीज है वह बाहर न भेजा जाये। मवेशियों पर गुजारा करने वाले लोगों को एक गाय के पीछे कम से कम 500 रुपये का कर्जा दिया जाना चाहिये। हमारी सरकार ने अकाल के मुस्तकिल इलाज के लिये लिफ्ट इरीगेशन स्कीमें बनाई थीं उनमें से लर्णकरन लिफ्ट इरीगेशन स्कीम को हाथ में लिया गया। उसकी तकमील हुई उससे बड़ा फायदा हुआ। बाकी जो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाथ में लिया जाना चाहिये। इससे हमारे रेगीस्तान का काफी हिस्सा काश्तकारी जमीन में बदला जा सकता है। मैं आखिर में इस बात की तरफ खास तौर पर तवज्जो दिलाऊंगा कि राजस्थान केनाल की तकमील के बाद सारे राजस्थान की अनाज की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। मगर अफसोस है कि हमारी सरकार के जमाने में बहुत रफ्तार से तरक्की हुई लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने इस काम को रोक दिया और ठप कर दिया। उसके बारे में अभी अपोजिट से बोलने वाले एक मेम्बर साहेब ने फरमाया था यह सीमेंट के अभाव की वजह से रुका। मैं अर्ज करूंगा कि सीमेंट जितना मिलता रहा वह भी उनके कर्मचारी और काम करने वाले लोग हड़प गये। इस तरह से इस बात का कोई इंतजाम नहीं किया गया कि उनको सीमेंट चोरी करने से रोका जाता और यह सरकार की गफ्लत की वहज से काम रुक गया। लेकिन मौजूदा सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी उस तरफ ज्यादा से ज्यादा काम किया जाये। मैं यह भी अर्जा करूंगा कि इसकी तकमील की तर्ज 1985–86 तक है मगर इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट मान कर सेंटर के जरिये जल्दी मुक्कमल किया जाना चाहिये। इतना कह कर मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दे कर बेठता हूं।

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने राजस्थान के पिछड़ेपन का जिक्र किया। कितना पिछड़ा है यह राजस्थान यह शायद इसी से प्रतीत होता है कि प्रेस दीर्घ

(श्री नत्थी सिंह)

खाली हो रही है, हाउस भी खाली हो रहा है। ऊधर मंत्री जी भी थक रहे हैं और आप भी चक्कर में हैं कि जल्दी से जल्दी पिंड छूटे। जब राजस्थान का नम्बर आया है तो इस राजस्थान की कितनी सुनवाई होगी इस पर मुझे शक है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पिछड़े हुए प्रदेश के इस बजट पर जब हम विचार करने जा रहे हैं तो यह देखें कि किन परिस्थितियों में विचार करने जा रहे हैं। यह भी बड़े खेद की बात है कि इस बजट पर राजस्थान विधान सभा में, जयपुर में आज विचार होता, लेकिन यह स्थिति बनाई गई, लोकतंत्र को पूर्ण आहुति दे कर उन्होंने यह स्थिति बनाई। मैं यह नहीं कहता कि इसकी शुरुआत उन्होंने की। उपसभाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लोकतंत्र को कमजोर कैसे किया जाये इसकी शुरुआत इससे पहले हो गई। चाहे कांग्रेस (आई) का शासन था या जनता पार्टी का शासन था, लेकिन आपकी स्वायत-शासी संस्थाएं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : नत्थी सिंह जी आपकी आवाज सुन कर काफी लोग आ रहे हैं।

श्री नत्थी सिंह : अच्छी बात है । मैं और ज्यादा उत्साह के साथ बोलूंगा । सुनिये क्यों घबड़ा रहे हैं। लकिन यहां भी एक बात बड़े जोरों से कही . . . . . (*Interruptions*) लेकिन उपसभापति महोदय, कभी-कभी जनतंत्र को मजबूत करने के लिये जरूरी है कि जनतंत्र का जो हमारा चरित्र है, हमारे देश का जो मानस है उसमें जनतंत्र को स्थापित्व किया जाय। लकिन जनतंत्र को लूला लंगडा बनाया जाता है और जनतंत्र पर जब आघात होता है तो देश के लोगों में उतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होती है जितनी होनी चाहिये। राजस्थान में कांग्रेस (आई) का राज्य था तो 13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। जनता पार्टी का राज्य आया तो पंचायतों के चुनाव हो गये। पंचायत समिति व जिला परिषद् को घोट कर मार दिया गया। वहां पर जो 13 वर्ष के पुराने चुने हुए लोग चल आते थे, कैसे भी थे उनको हटा कर सरकारी अधिकारी बैठा दिये गये। जनता राज में लोकतंत्रीय की हत्या हुई। सारे कोआपरेटिव इंस्ट्रीट्यूशंस भंग कर दिये गये उन पर एडमिनिस्ट्रटर्स बैठा दिये गये। सारी कोआपरेटिव समितियां भंग कर दी गयी, उन पर प्रशासन थोप दिया गया। इसी तरह से सारी कृषि मंडियों के साथ हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछले राज्य में स्वायत्त-शासी संस्थाओं की, लोकतंत्र की हत्या करने की विधान सभाओं को भंग करने की शुरूआत की गयी थी उसकी पूर्ण आहुति कांग्रेस (आई) ने की। दूसरी बात जो मैं उपसभापति महोदय, कहना चाहता हूं मुझ मालूम है कि विधान सभाओं को भंग करके कह रहे हैं कि बजट पर वोट आन एकाउंट है, चार महीने के लिये ले रहे हैं। लेकिन दो चर्चाएं चल रही हैं बड़े जोरों से । एक चर्चा चल रही है कि बड़ी जल्दी मई में विधान सभा के चुनाव करा देंगे । लेकिन एक कानाफूसी यह भी चल रही है कि विधान सभाओं के चुनाव मानसून के बाद टला दिये जायें। ये कांग्रेस (आई) के कुछ लोग इस बात का प्रचार कर रहे है। अब मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मान लिजिये आपने यह फैसला किया। हालांकि पता नही आप क्या फैसला करेंगे। आज कुछ देंगे, कल कुछ कह देंगे। फैसला जब भी करोगे लेकिन फैसला यह किया कि अपने चुनाव मानसून में होंगे तो क्या यह जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट

राजस्थान में है, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत क्या आप यह करोगे कि नवम्बर, दिसम्बर को विधान सभा के चुनाव हटा दो और तब तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं होंगे, कोआपरेटिव चुनाव नहीं होंगे, नगरपालिका के चुनाव नहीं होंगे, कृषि मंडियों के चुनाव नहीं होंगे। यदि आप जल्दी विधान सभाओं के चुनाव करा रहे हैं तब तो बात दूसरी है। लेकिन दूसरी जो साजिश चल रही है कि चुनाव बढ़ा दो तो इन स्वायत्त शासी संस्थाओं के चुनाव शीघ्रतम होने चाहिये। एक बात और कहना चाहता हूं कि किस तरह से लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान में जो कुछ आफिसर थे, मैं जानता हूं, जिन्हें शायद मंत्री महोदय भी जानते हैं, राज्य मंत्री वहां जाते हैं, उन विभाग में एक सनक सवार हुई है कि यहां जो बैंक कोआपरेटिव सिस्टम है, लैण्ड डेवलपमेंट सिस्टम है यह अलग नहीं होने चाहियें और इनको मिल कर एक कर दो। आज चुने हुए लोग नहीं है इन संस्थाओं में इसलिये जल्दी हो रही है। पिछले मंत्री ने भी यही किया था, जनता राज के जो मंत्री थे वे भी उस समय जल्दी कर रहे थे। चुने हुए लोग नहीं थे उससे पहले संस्थाओं का एकीकरण कर दो। पता नहीं आज जो थोड़ा बहुत लोन लोगों के लिये मिल जाता है; अगर आज एल० डी० और सी० सी० बैंक को एक कर दिया गया, एक टैक्टर एक गांव में दे दिया गया और वे डिफाल्टर हो गये तो पूरी सोसाइटी को न तो खाद के लिये ऋण मिलेगा न बीज के लिये। इसलिये मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि जब तक इन स्वायत्त-शासी संस्थाओं में चुने हुए लोग न आ जायें तब तक अफसरशाही की मनमानी नहीं चलनी चाहिये कि वे बिना चुने हुए लोगों की राय जाने इस तरह का स्ट्रक्चरल चेंज कर दें। जिसको रिजर्व बैंक ने मना किया है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट बोर्ड जो रिजर्व बैंक का है उसने प्रस्ताव किया है कि नहीं होना चाहिये। लेकिन पिछली बार जो राजनीतिक कारणों से दबाव डाला जा रहा है उसी परम्परा को आप भी निभा रहे हैं। यह एक बात है जो मैं कहना चाहता हूं।

दूसरी बात जब आपकी सरकार बनी। चुनाव में आप गये तो बड़े जोरों से यह बात कही गयी कि इस देश में अगर अराजकता मिटानी है, स्थिर सरकार लानी है तो इन्दिरा जी को वापस लाओ, देश को बचाओ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अराजकता मिट गयी। आज राजस्थान में क्या हालत है ला एण्ड आर्डर की। सारे राजस्थान में आज डकैतियां, चोरियां, हिंसा, हत्या लूट-पाट का दौर है। जिस जिले से हमारे मंत्री जी आते हैं और मैं आता हूं वहीं की मेरे पास लिस्ट है। अगर गिनाऊं तो 18 फरवरी को हमारे यहां विधान सभा भंग हुई। 20-21 फरवरी को इस जिले में 12 ट्रक लूट लिये गये। 15 मार्च को बयाना के महराक ग्राम में बृजवासी गूजर को गोली से उड़ा दिया गया। आइये यह किस्सा बजट पर सुन लीजिये। यह तो जानिए बजट में क्या क्या आता है। तो आप यह समझिए कि यह पुलिस बजट इसलिए मंजूर हुआ है। मालूम है कि नहीं आपको। ला एण्ड आर्डर भी इसमें है। इसी तरह फिर नांगल गांव में बन्नो सरपंच के यहां तीन लाख की डकैती हुई। अधपुर में बरपुरा गांव में जाटवों के यहां डकैती हुई और यहां 50 हजार का माल लूटा गया। धौलपुर के लिए पिछले मंत्री ने गवर्नर मोहोदय को एक लम्बा चौड़ा ज्ञापन दिया है। इसी तरह से कुम्हेर तहसील में खेड़वार गांव में, कुरवारा गांव में, सिरसई गांव में रोज डकैतियां हो रही हैं। एक गांव कुरवारा में जब

[श्री नत्थी सिंह]

पांच घरों में डकैती पड़ी, जो बेचारा हरिजन होता है, मेहतर होता है, उनके यहां भी डकैती पड़ी। थानेदार महोदय वहां गये। पाड़िया साहब, आप पुलिस को कैसे रिओरिएंट कर रहे हैं? उन्होंने जाकर कहा, तु तो भंगी जाति का है, तेरा पक्का मकान है, तो डकैती नहीं होगी तो और क्या होगा? मैं भी उस गांव में गया। मुझे शर्म आई जब हरिजन ने कहा कि मुझे पूरा दिला। गांव के बाहर झोंपड़ी डाल लूं क्योंकि थानेदार कहता है कि पक्का मकान बनाओगे तो तुम्हारे यहां डकैती नहीं होगी तो और क्या होगा। उस गांव में पांच दिन के बाद फिर डकैती पड़ी। इस तरह की स्थिति हो रही है। यही नहीं, अभी एक गांव में जो आपके क्षेत्र में ही है, जहांगीर पुर गांव, वहां एक अनुसूचित जाति बावरिया के आदमी ने प्रधान मंत्री को दर्खास्त भेजी, गवर्नर को दर्खास्त भेजी, कमिश्नर आफ पुलिस को दर्खास्त भेजी और फिर होम मिनिस्टर महोदय को मैंने लिखा, तो क्या हुआ? वह जगनेर का थाना जो यू० पी० का है, वहां आता है। वहां तो झगड़ा किसी और तरह का है। उसके दामाद को ले जाते हैं, उसके बेटे को ले जाते हैं, केस भी दर्ज नहीं करते और वहां जाकर उनको फर्जी एन्काउन्टर दिखा कर जान से मार दिया जाता है। इस तरह से कैसे सुरक्षा दी जाएगी।

तो मैं कहना चाहता हू कि इस स्थिति को बदला जाना चाहिए और यदि इस स्थिति को बदलोगे नहीं तो लोगों के दिलों से आतंक नहीं जायेगा और आतंक नहीं जायेगा, तो जो आपने नारा दिया था, इस नारे के साथ आप इन्साफ नहीं करेंगे। वह केवल नारा ही बन कर रह जाएगा। इसके साथ दूसरी समस्या जो राजस्थान में है वह है ला एण्ड आर्डर की। वहां आज स्थिति यह है कि लोग जिन्दा कैसे रहें, जीवन-यापन कैसे करें। आप जानते हैं कि अभी हमारे उस्मान आरिफ साहब कह रहे थे कि सब से बड़ी भयंकर स्थिति राजस्थान में सूखे की है। सूखा इतना पड़ा है कि लोगों को मुश्किल हो गई है। कुछ लोगों ने बड़ी मुश्किल से डीजल लिया। एक सौ रुपये या रु० 125 में एक कैन खरीद कर लाए ब्लैक में और उससे कुछ फसल भी की।

बिजली का हाल यह है कि किसान को बिजली नहीं दी गई, कटौती होती चली गई और आज भी यह स्थिति है कि उससे मिनिमम चार्जेज तो मांगे जा रहे हैं, उस सूखे के इलाके से, लेकिन उस किसान को जिसकी फसल नष्ट हो गई, उसको कोई मुआवजा देने का सवाल नहीं है। उसके साथ-साथ हमारे राज्य में और विशेषकर हमारे जिले में सारी मेहनत के बाद किसान की फसल पर ओले पड़ गये। अभी हमारी माननीया सदस्या श्रीमती अमरजीत कौर कह रही थीं फसल बीमा की बात। बहुत दिनों से हम और आप यह बात चला रहे हैं। वह बातों में ही टाल दिया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान ने इतनी मुश्किल से फसल उगाई, ब्लैक में मैटीरियल खरीदा, बिजली नहीं मिली, तब भी किसी तरह से उसने काम चलाया। आज जब ओले पड़ गये तो उसकी सारी फसल नष्ट हो गई और जब कलेक्टर के पास लोग गये, बहुत बड़ी-बड़ी शिला ओले को उठा कर लाए, तो वह बेचारा कहता है कि कोई प्रावधान नहीं है इस सरकार में किसी तरह की मदद देने का। मैं क्या करूं, ऊपर लिखूंगा। ओले अगर पड़ जाए तो साल भर वह किसान भूखों मरेगा। तो मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि वह बेचारा एक साल तक गुजारा नहीं कर सकता। उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैंने पिछली बार संसद में कहा था, सामान्य बजट की चर्चा में भाग लेते हुए कि आप दूसरों की बुराई क्यों करते हो। अभी कह रहे थे कि जनता पार्टी की अन्त्योदय स्कीम अच्छी

नहीं थी, फूड फार वर्क स्कीम अच्छी नहीं थी। पर जो चीज अच्छी थी, उसे तो सीखो। इसी हरियाणा में श्री देवी लाल जी ने प्रावधान किया था कि यदि किसानों की प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होगी, ओलों से या आग से तो उनको तीन सौ रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा सरकार देगी। क्यों नहीं उसको सीखते, उसकी नकल करते और जो लोग ओलों से बरबाद हो गये हैं, उनके जीवनयापन के लिए तीन सौ रुपये के हिसाब से आप मुआवजा दे दें। मैं चाहता हूं कि इस बात की ... *(Interruptions)*

श्री प्रभु सिंह (हरियाणा) : हरियाणा सरकार तो दे रही है, अपनी सरकार से कहिए।

श्री नत्थी सिंह : यही तो मैं कह रहा हूं कि आप भी उसकी नकल करिए। इसके साथ-साथ मंत्री जी जानते हैं कि राजस्थान में किस तरह की दिक्कत में लोग हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो सूखे के संबंध में जो पीड़ा है, पीने के पानी के बारे में स्थिति यह है, पश्चिमी राजस्थान में ही नहीं, भाभड़ा साहब भी कह रहे हैं, हम पूर्वी राजस्थान के लोगों को पता है कि हमारे यहां भरपूर पीने का पानी भी नहीं है। आज बिजली की क्या हालत है? बिजली वाले लोगों के पास किसान गये अभी दस दिन पहले और कहा कि हमारे जिस क्षेत्र में पानी मीठा निकलता है, वहां कनेक्शन दीजिए। आज कनेक्शन जहां दे रखा है वहां खारा पानी है। हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं जहां मीठा पानी है, वहां ताकि हम अपना पशु-धन बचा सकें पीने का पानी ले लें, तो क्या कहते हैं कि ये टार्गेट तो पूरे हो गए, अब हमारे पास साधन नहीं हैं। हमारे नियम इजाजत नहीं देते हैं और हम नियमों को बदल नहीं सकते हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा, सूखे की और अकाल की जो भीषण विपत्ति हमारे प्रदेश में है उसको देखते हुए, पीने के पानी का मीठा स्रोत जहां है वहां बिजली की सप्लाई के लिए भी विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। किसान और पशु बिना पानी के कैसे जिन्दा रहेंगे? यह परिस्थिति हमारे प्रदेश में है।

मैं एक बात की ओर विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं, राहत कार्य के संबंध में। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं यह ऐसा काम है जो अगले चुनाव तक या अगली सरकार आने तक नहीं रोकना चाहिए, फौजी तौर पर और तुरन्त करना चाहिए नहीं तो जान और माल का खतरा हो जाएगा। राहत कार्य सालों चलते रहेंगे ठीक है, काम के बदले अनाज की योजना भी है लेकिन पहले 5–6 किलो मिलता था। और आज अकाल राहत कार्य हो रहे हैं तो सरकार ने कह दिया अभी तीन किलो अनाज देंगे और 50 पैसा देंगे। कोई काम बड़े तो खोले नहीं और किसान के पास कुछ रहा नहीं। उसकी मजदूरी पहले से काम कर दी, यह कहां का न्याय है? इसलिए कोई दकियानूसी बातें मुल्क में चल रही हैं तो आप उसके लिए नियम बदल दें। मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले, इसके लिए राहत कार्य किए जाएं, मजदूरों को मजदूरी सही दी जाए, अनाज दिया जाए। तब जाकर काम चलेगा।

आज बिजली की कमी की वजह से सारे उद्योग धन्धे बन्द हो गए। केसरी साहब आप क्या इशारा कर रहे हैं? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के बारे में कहूंगा, तो आपको सुनना होगा। करो या नहीं करो दूसरी बात है ... *(Interruptions)* ... मैं कहना चाहता हूं, बड़ा से बड़ा राहत कार्य वहां करें जहां अकाल है जिससे कृषि मजदूरों को, किसानों को, पब्लिक को सहारा मिले और अपना जीवन यापन कर सकें। यह बहुत जरूरी है।

राजस्थान अकाल से पीड़ित प्रदेश है, हर बार, तीसरे साल, अकाल की छाया आती

[श्री नत्थी सिंह]

हैं। उसका स्थायी इलाज क्या है ? स्थायी इलाज है सिंचाई के साधनों का विकास। आज पानी के स्रोत हैं हैड वर्क्स—हमारे सुलतान सिंह जी भी चिल्लाते-चिल्लाते बुड्ढे हो गए हैं और मैं भी खूब चिल्लाया। सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला दे दिया लेकिन पंजाब वाले अकड़ गए—उनका कंट्रोल—भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड का क्यों ट्रान्सफर नहीं कर रहे हैं। तो हमारी मांगों को कब तक नहीं मानोगे। मैं चाहता हूं यह हैंड्स का जो नियंत्रण है उसके बारे में नियमानुसार जो अवार्ड हुआ है उसका पालन किया जाना चाहिए। दूसरी बात . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): नत्थी सिंह जी, आपने सुल्तान सिंह साहब को बूढ़ा कह दिया। अपने बारे में कुछ कहा नहीं।

श्री नत्थी सिंह : मेरे तो बाल ही सफेद हैं . . . *(Interruptions)* एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिसमें हरियाणा वाले भी शोषण करते हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी हमारा शोषण करते हैं और वह है जब बाढ़ आएगा तो जमुना का पानी जाएगा हमारे इलाके में .

श्री प्रभु सिंह : हम उनका साथ देते हैं। हम आपका साथ दे रहे हैं

श्री नत्थी सिंह : धन्यवाद। बाढ़ आती है तब तो हम को डुबा देते हैं और जब बाढ़ नहीं आती है तो पानी नहीं देते हैं। यहां गंगा के पानी का प्रश्न मैंने पिछली बार उठाया था, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हमारे सदन के नेता कमलापति त्रिपाठी जी थे। वे बीच में खड़े हो गए कि गंगा के बेसिन में पानी नहीं है। तो हमें डुबाने के लिए पानी कहां से आता है ? अगर टेहरी डैम बन जाता तो रेगिस्तान के इलाकों को गंगा का पानी मिल जाता। एक बार यू० पी० के मिनिस्टर आए इसलिए एक बार पानी मंगाया गया। सो पशुओं के लिए पानी, यमुना का पानी हमें मिलना चाहिए। ओखला जो बन्द है उसको बनाने के लिए साढ़े 18 करोड़ रु० का प्रावधान हैं। राजस्थान ने अपने हिस्से का पैसा देने के लिए साढ़े तीन करोड़ रु० का वायदा किया। आज तक येन केन कोई न कोई बहाना बना कर, उसको नहीं बनाया जा रहा है। जब तक वह बनेगा, हमारे गुड़गावां कैनाल से कुछ प्रावधान हो सकता है, लेकिन पानी तो मिलता नहीं है। भरतपुर फीडर है, उस में बड़ी मुश्किल से एक यू० पी० के मिनिस्टर आए थे, इसलिए एक बार पानी मंगाया गया, सो भी पशुओं के काम आया। फसल के लिए पानी मिला नहीं। हम तो बृज के रहने वाले हैं, हमारी मांग है कि गंगा सारे देश की है, यमुना सारे देश की है। जब हमारे लिए स्कीम बन सकती है तो प्रावधान क्यों नहीं है ? क्यों नहीं राजस्थान को गंगा और यमुना से पानी का हिस्सा दिया जा रहा है ? यह बड़ी जरूरी बात है। आज स्थिति यह हो गई कि हमारे यहां गंगा कैनाल जो पुराना बना है वह भी जर्जरित हो गया है। राजस्थान कैनाल को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं मानोगे तो राजस्थान कैनाल से पूरे कार्य नहीं कराए जा सकेंगे। नेशनल प्रोजेक्ट मानोगे तो निश्चित रूप से राजस्थान कैनाल को हम शीघ्रता से पूरा कर सकते हैं।

मैं एक बार उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए सदन में कहना चाहता हुं कि अभी हमारे उस्मान आरिफ साहब कह रहे थे —बहुत सही बात उन्होंने कही है—नेशनल केलेमिटी के नाम पर सात करोड़ रु० मंजूर कर दिया, क्या होगा उससे ? राजस्थान ने 100 करोड़ रु० मांगे। उसी बात का मैं समर्थन करता हूं और निश्चित रूप से इस को बढ़ाया जाना चाहिए। एक बात और . . .

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : काहे का ?

श्री नत्थी सिंह : नेशनल केलेमिटीज के लिए सात करोड़ का प्रावधान काफी नहीं है। पहाड़िया जी, मैं सुनता हूं कि आप राजस्थान में जाने का मन रखते हो। अगर मन है तो

अभी कुछ प्रावधान करा लो, फिर गड़बड़ हो जायेगा ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि राजस्थान औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जैसा माननीय सदस्य भाभड़ा साहब ने कहा, केवल राजस्थान में केन्द्रीय सहायता का 2.11 परसेंट खर्च हुआ है। क्यों नहीं हमारे यहां सरकार अधिक से अधिक सहायता देती? हमारी मांग रही है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाय, लेकिन नहीं हो रहा। आज ट्रकों का कारखाना है तो वह भी वापस जायेगा। यही स्थिति है चाहे सीमेंट का हो या खाद का हो। बहुत पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी वहां के मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने भारत सरकार से मांग की थी कि ड्राई पोर्ट भरतपुर में बनाना चाहिए और उसके लिए भरतपुर सबसे मौजूं जगह है। यह बात उन्होंने कही, लिख कर भेजा, विचार भी हुआ। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आयी राजस्थान में। उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि भरतपुर में ड्राई पोर्ट बनना चाहिए। बात क्या है कि ध्यान नहीं दिया जाता? आज जब मथुरा में आप तेल-शोधक कारखाना जल्दी से जल्दी बनाने जा रहे हैं तो भरतपुर सबसे मौजूं जगह है कि वहां ड्राई पोर्ट बने ताकि रोजगार मिले, यातायात के साधन बढ़ें और माल ढोने में सुविधा मिले। तो मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज राजस्थान पिछड़ा हुआ है, चाहे ग्रामीण विद्युतीकरण हो, चाहे शिक्षा का मामला। गरीबी में भी हम सब से नीचे हैं, हमारी औसत आमदनी 750 है जब कि देश की एवरेज 850 है। इसलिए राजस्थान के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। चाहे गाडगिल फार्मुला हो या और कोई फार्मुला, अगर आप चाहते हैं कि देश में अनइवेन विकास न हो, एक-सा विकास हो तो निश्चित रूप से इन फार्मूलों में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा।

मै एक दूसरी बात आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और वह है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : दूसरी नहीं, आखिरी होनी चाहिए।

श्री नत्थी सिंह : जो आपका हुक्म। मुझे जो बताया गया है उसके अनुसार समय है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): 22 मिनट हो गये।

श्री नत्थी सिंह : आप वोट आन एकाउन्ट ले रहे हैं, आप कहेंगे कि बड़ी योजनाओं के बारे में न कहो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप ने यह स्कीम बनायी राजस्थान की तो आपको मालूम रहा होगा कि सिंचाई के विस्तार की जरूरत है। आप ने 325 करोड़ रुपये का प्लान रखा है। और उसमें कृषि और लघु सिंचाई योजनाओं पर 51 करोड़ रुपये, केवल 15.7 परसेंट रखा है। यह आप का कौन सा दृष्टिकोण है। क्यों नहीं आप प्रायोरिटी देते और ज्यादा धन इस योजनाओं पर खर्च करते जिस से राजस्थान का समग्र विकास हो सके। सिंचाई के साधन नहीं होंगे तो राजस्थान विकसित नहीं होगा। राजस्थान में पशु-धन और कृषि दोनों के विकास की बहुत सम्भावना है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जब तक इस ओर पूरी तरह ध्यान नहीं जायेगा।

मैंने साफ तौर पर कहा है कि जो फौरी समस्याएं हैं उनका तुरन्त समाधान हो। मैं कहना चाहता हूं कि आज सूखे से पीड़ित हैं हम, ओलों से पीड़ित हैं हम, उससे भी पहले बाढ़ से पीड़ित थे हम, बहुत बाढ़ आयी थी, लेकिन आज वसूलियां हो रही हैं, नोटिस दिये जा रहे है, सरकारी और सहकारी ऋणों की वसूली के नोटिस दिये जा रहे हैं। उस के पास खाने को नहीं, अगली फसल कैसे पकड़े

[श्री नत्थी सिंह]

उसके साधन नहीं, राहत कार्य मिल नहीं रहे और हम इतने भावनाहीन हो चुके हैं कि उसे नोटिस दे रहे हैं तुम पैसा वापस करो नहीं तो तुम्हारा जो कुछ है उसे कुर्क कर लिया जायेगा। इसलिए इस तरह की सारी कार्यवाहियों को बन्द किया जाना चाहिए, जिससे गरीब लोगों के दिमाग में यह भावना न आये कि हमारी जो असली समस्याएं हैं उनके प्रति सारा शासन बेखबर है, उदासीन है, सिर्फ वोट लेने के वक्त हर आदमी आता है—मैं लाया नहीं हूं, वह पर्चा मैंने पहले दिखाया था—सारा हिन्दुस्तान का नक्शा बदल रहा है, ऐसे नारे थे, लेकिन अब न डीजल मिलेगा, न तेल मिलेगा और चीनी के भाव तो कहां से कहां जा रहे है। आज अराजकता बढ़ रही है। ओलो वालों को मुआवजा नहीं देंगे तो आप देश का उद्धार कैसे करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन ज्वलन्त समस्याओं पर, जिन से आज किसान, मजदूर, गरीब लोग पीड़ित हैं, ध्यान दें और उनके लिए राहत के काम शुरू करें और उन्हें राहत दिलायें। तभी इस बजट के सही रूप में कुछ मायने होंगे। वरना इसकी क्या तुक है कि 30–32 साल के बाद राजस्थान में 2.11 परसेंट खर्चा हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है। दृष्टिकोण में बदलाव के साथ-साथ हम जिस गरीब आदमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसकी वास्तविक रूप से मदद होनी चाहिए। अगर उसमें नियम आड़े आते हैं तो उन नियमों को बदला जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : महोदय, पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट में एक प्रोवीजन है कि कितने हेडवर्क्स पंजाब के हैं जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पानी का बटवारा होता है उन हेडवर्क्स के ऊपर भाखड़ा मैनेजिंग बोर्ड का कब्जा होगा लेकिन 1966 में यह एक्ट पास हुआ और आज तक उन हेडवर्क्स पर पंजाब का कब्जा है और इसमें राजस्थान सबसे ज्यादा सफर करता है।

जहां तक राजस्थान कैनाल का ताल्लुक है मैं आपकी मार्फत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि नान-प्रिमियल वाटर इतना है कि व्यास और सतलुज का बशुमार पानी बरसात के मौसम में पाकिस्तान को जाता है जो पानी पाकिस्तान को जाता, वह पानी ईजिली राजस्थान के अन्दर जा सकता है अगर सरकार वारफुटिंग पर और *नेशनल प्रोजेक्ट मानकर राजस्थान* कैनाल को पूरा करे।

इसके साथ ही एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं। अभी नत्थी सिंह जी ने फरमाया कि यमुना रीवर का पानी उनको मिलना चाहिये। उनको याद होगा कि बहुत पहले एक प्रोजेक्ट बना था यमुना के ऊपर डैम बनाने का, किसाऊ डैम बनाने का। यमुना एक ऐसी रीवर है जिसके ऊपर अभी तक कोई डैम नहीं है और जमुना में बरसात के मौसम में इतना पानी आ जाता है कि दिल्ली को भी खतरा हो जाता है डूबने का और जब गर्मी आती है तो उसमें इतना कम पानी रह जाता है कि दिल्ली में ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रोबलम हो जाती है। अगर किसाऊ डैम बन जाता तो कितना पानी राजस्थान को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा, उत्तर प्रदेश को मिलेगा, यह सब डिसाइड हो जाएगा। आज 15–20 साल हो गये हैं उस प्रोजक्ट को अप्रूव हुए उस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। अगर यमुना के ऊपर किसाऊ डम बन जाता है तो राजस्थान के अन्दर इरीगेशन का काम अच्छा हो सकता है। यमुना रीवर के ऊपर दो हेडवर्क्स हैं एक ताजवाला और दूसरा ओखला बैरेज। दोनों इतने पुराने हैं कि सिल्टिंग जमा हो जाती है और उसकी वजह से जितना अच्छे ढंग से सुचारू रूप से पानी चलना

चाहिये वह नहीं चल सकता । मैं आपकी मार्फत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान को पानी देने के लिए यमुना के ऊपर किसाऊ डैम का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए । इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ताजावाला हेडवर्क्स और ओखला बरेज इन के लिये भी एक एग्रीमेंट हो चुका है । उत्तर प्रदेश के साथ उनके रीमोडल करने का । लेकिन आज तक वह रीमोडल नहीं हुआ है । इसी की वजह से राजस्थान में जो पानी जाता है आगरा केनाल के थ्रू वह पानी पूरा नहीं जाता जितना राजस्थान को जाना चाहिए । आपकी मार्फत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि ओखला बैरेज को रीमोडल किया जाए, आगरा केनाल की लाइनिंग हो । आगरा केनाल ऐसा है कि जिसके दोनों तरफ वाटर लोगिंग हो जाता है और राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिल पाता है। अगर आगरा कैनाल की लाइनिंग हो जाए और ताजावाला और ओखला बैरेज का रीमोडल हो जाए तो राजस्थान में इरीगेशन बढ़ सकता है । अगर सरकार चाहती है कि राजस्थान में इरीगेशन बढ़ तो सरकार को चाहिये राजस्थान केनाल को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि व्यास और सतलुज का पानी जो बरसात के मौसम में पाकिस्तान को चला जाता है वह राजस्थान को मिल सके । जहां तक हेडवर्क्स का ताल्लुक है जिसमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का ज्वाइंट हिस्सा है उनका कब्जा भाखड़ा मैनेजिंग बोर्ड के पास हो ताकि बटवारे में कोई हेरा-फेरी न हो। यही मैं आपकी मार्फत सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, राजस्थान की समस्या बहुत गम्भीर बतलाई गई है, लेकिन माननीय सदस्यों ने उसी गम्भीरता के साथ राजस्थान के बजट पर विचार नहीं किया । श्री नत्थी सिंह जी ने राजस्थान का दौरा करने की बात कही । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह सेशन समाप्त होने के बाद मैं राजस्थान का दौरा करूंगा । उसमें उनका स्वागत है। वे मेरे साथ चल सकते हैं।

श्री नत्थी सिंह : मैंने तो और तरह से चलने की बात कही थी ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : पहेलियां बुझाने का काम मेरा नहीं है । मैं तो सीधा और सच्चा आदमी हूं । उनका क्या इरादा है, यह मैं नहीं जानता । मैं सिर्फ उनको निमंत्रण ही दे सकता हूं ।

माननीय सदस्यों ने राजस्थान के बजट के सिलसिले में बहुत सी बातें कही हैं । मैं चाहता हूं कि मैं उन सब बातों का जवाब दूं । माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं और जो अच्छे सुझाव दिये हैं, मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा । लेकिन एक बात मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर किसी के दिमाग में यह गलतफहमी पैदा हो कि केन्द्रीय सरकार का ध्यान राजस्थान के विकास की तरफ नहीं है और वह जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह तो अपने अपने ढंग से विचार करने का तरीका है। लेकिन केन्द्रीय सरकार की हमेशा से यह राय रही है कि जो पिछड़े इलाके हैं, चाहे वह राजस्थान हो या अन्य कोई क्षेत्र, उनको हर संभव सहायता दी जाती है । बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अन्य क्षेत्रों के अनुपात में यथा-संभव उनको ज्यादा सहायता दी जाये । यह बात आंकड़ों से भी साबित की जा सकती है। इस साल के बजट पर अगर आप विचार करें तो आपको पता चलेगा कि इस साल के बजट में पिछले साल की बजट की तुलना में ज्यादा धन का प्रावधान किया गया है । पिछली सरकार ने जो प्रावधान किये थे उससे हमने ज्यादा प्रावधान किये हैं । जिस तरह से पिछली सरकार राजस्थान में चल रही थी वह ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही थी । मैं श्री नत्थीसिंह जी की

[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

इस बात का समर्थन करता हूं कि पिछली जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर लोकतंत्र का गला घोंटा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमने भी वहां की एसेम्बली को भंग करके लोकतंत्र का गला घोंट दिया। मेरे ख्याल से वे भी इन सब बातों में भागीदार हैं। जब जब भी इस प्रकार की घटनायें होती हैं उनमें वे भी भागीदार हैं। वास्तव में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र का असली मायने क्या होता है। शायद वे इस बात को नहीं समझते हैं। लोकतंत्र का तकाजा यह है कि समाज का, राज्य का और देश का विकास ठीक ढंग से हो सके। देश में जो गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके और चाहे काश्तकार हों, मजदूर हों, विद्यार्थी हों, व्यापारी हों, उन सब के साथ ठीक ढंग से व्यवहार हो सके। चूंकि पिछली राजस्थान की सरकार ने ये सब काम ठीक ढंग से नहीं किये, इसीलिए इस प्रकार के कदम उठाने पड़े। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारे इस बजट में उन सब बातों की व्यवस्था की गई है और वे सब कदम उठाये गये हैं जिससे राजस्थान का विकास शीघ्र हो सके।

माननीय सदस्यों ने अनेक बातें बतलाई। मैं उनका एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। सब से पहले मैं बतलाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड सर्विसेज के लिए 1979-80 के बजट में जहां पिछले साल 31.92 करोड़ रुपयों की व्यववस्था की गई थी वहां इस बजट में उनके लिए 50.64 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार वह लगभग 20 करोड़ रुपये ज्यादा है। इसी तरह से कोआपरेटिव सेक्टर के लिए इसी 3 करोड़ रुपयों की व्यवस्था थी, अब पहले तीन करोड़ 82 लाख रुपये कर दिया इसको। इसको 82 लाख अधिक कर दिया गया है जहां तक वाटर पावर डेवलपमेन्ट का सवाल है, उसके लिये पिछले बजट में 171 करोड़ 40 लाख रुपयों की व्यवस्था थी, लेकिन अब इसको 189 करोड़ 45 लाख कर दिया गया है। इसी तरह से इन्डस्ट्री और मिनरल में भी पहले 11 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन अब उसको बढ़ा कर 11 करोड़ 51 लाख कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए पहले 21 करोड़ 50 लाख का प्रावधान था लेकिन अब इसको 23 करोड़ 10 लाख कर दिया गया है। इसी प्रकार से सामाजिक सेवाओं के लिए पहले 35 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन अब उसको 44 करोड़ 52 लाख कर दिया गया है। इसी प्रकार से सर्विसेज में पहले जो एक करोड़ 10 लाख का प्रावधान था उसको बढ़ा कर एक करोड़ 15 लाख कर दिया गया है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पिछले बजट में जो 275 करोड़ का घाटा था वह अब 325 करोड़ रुपयों का हो गया है और यह बढा है। इसीसे आप सब बातों का अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि जो बढ़ोत्तरी हमने राजस्थान के विकास के लिये की है, हम आशा करके चलते हैं कि राजस्थान सरकार को सभी वर्ग के लोगों का सहयोग मिलेगा जिससे कि विकास के काम जो चल रहे हैं उसमें और तेजी आ सके।

श्री भाभड़ा ने अपने भाषण में केन्द्रीय सहायता की चर्चा की है। इस चर्चा को करते समय शायद वे अपनी सरकार के पुराने आंकड़े देखना भूल गये केवल आज की सरकार के ही आंकड़े उन्होंने देखे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1977 में असेम्बली में उन्होंने किस तरह से हमारे साथ सलूक किया और .....

श्री हरी शंकर भाभड़ा : मैंने जब कुछ नहीं कहा तो आप क्यों याद कर रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने कहा कि याद कराना पड़ेगा .....

श्री हरी शंकर भाभड़ा : मैंने तो सजेशन दिये हैं और कंसट्रक्टिव सजेशन देता हूं।

I do not want to enter into politics. If you want, I am prepared for that also.

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं यह केवल आपकी जानकारी के लिये दे रहा हूं कि पिछले बजट में केन्द्र की सरकार ने, जो आपकी सरकार थी, उसको 54 करोड़ 45 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये। इस साल हमने 62 करोड़ 31 लाख रुपये का प्रावधान किया है केन्द्रीय सहायता के रूप में।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : पहाड़िया जी, मैंने आपकी सरकार और अपनी सरकार की बात नहीं की। यह आपका जो रवैया है यह आप बदल दें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपने नहीं आरिफ साहब ने यह बात कही है।

इसी प्रकार के आई०ए०डी०पी० में पिछले साल के बजट में 20.72 लाख का प्रावधान था जब कि इस समय 23.83 का प्रावधान है। इस तरह से आप देखेंगे कि केन्द्रीय सहायता में हमने बढ़ोतरी की है। पर कैपिटा प्लान असिसटेन्स पिछले साल 44 थी जो अब बढ़ कर 45 हो गई है। कम से कम एक आंकड़ा बढ़ा तो हैं और कुल मिलाकर जो हमारे राज्यों का अनुपात है उसके मुकाबले राजस्थान पहुंच गया हैं। यह कहते हुए खुशी है परन्तु सन्तोष की बात नहीं है। राजस्थान पिछड़ा हुआ है और वहां बहुत कुछ करना है। वहां पर पिछड़े इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, ट्राइवल्स एरियाज हैं, उनके लिये हमें बहुत कुछ करना है इसमें कोई शक-शुबहा है नहीं परन्तु इसमें समय लगेगा और जब नई सरकार वहां। आयेगी तो वह इस ओर ध्यान देगी। श्री आनन्द जी ने कहा पंजाब के बजट के समय कि पुलिस के सारे सरकारी कर्मचारी कांग्रेस (आई) के हुक्म को मानने लगे हैं। यह केवल आलोचना के तौर पर आप कहते हैं। आप इतना भूले और भटक जाते हैं पर जो होने वाला है भविष्य में उसको देख लेते हैं। इसलिये अच्छा है कि मिलकर सब को काम करना चाहिये।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : आप ज्योतिषी बनने जा रहे हैं क्या?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आनन्द जी की बात कर रहा हूं।

इसी प्रकार से उन्होंने पब्लिक सेक्टर इनवेस्टमेन्ट की बात कही। तो पब्लिक सेक्टर इनवेस्टमेन्ट पिछले साल जो कि करीब 56 करोड़ 3 लाख था हमने उसको बढ़ा करके करीब 300 करोड़ कर दिया है। लगभग इसलिये कहता हूं कि पिछले आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। मैं आशा करके चलता हूं कि भविष्य में यह प्रयास किया जायेगा कि जो पिछड़े इलाके हैं उनका विकास हो।

राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है। इसलिये हम रेगिस्तान के विकास के लिये जो पिछली सरकार का काम रहा है उस काम को बराबर बढा रहे हैं। इसमें हमने 80 लाख रुपये की बढ़ोतरी की है ताकि रेगिस्तानी जो इलाका है उसका विकास इस ढग से हो सके जिससे वहां रोजगार के अवसर भी बढें और खेती ड़ी बकी व्यवस्था भी हो।

इसी प्रकार से ट्राइवल एरिया डेवलपमेन्ट के लिये भी हमने बजट में प्रावधान रखा है। लेकिन मैं इसके आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपने आदिवासियों के मामले में कोई चिंता नहीं दिखाई है। मेरा ख्याल है कि शेडयूल्ड कास्ट के बारे में आप लोगों ने चर्चा की है। उसमें करीब पिछले साल के बजट के अन्दर 4 करोड़ 94 लाख रुपये का प्रावधान था इसको बढ़ा कर हमने 5 करोड़ 25 लाख रुपया किया है। बढ़ोतरी जिस

[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

अनुपात में होनी चाहिए थी मैं यह मानता हूं कि वह नहीं है लेकिन जैसे जैसे काम होता जायेगा और अगर जरूरत हुई तो इसको बढ़ाया जा सकता है ।

श्रीमन, राजस्थान केनाल की चर्चा यहां पर हुई । मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हैं कि इस साल के बजट में हमने पिछले साल के बजट के मुकाबले में कुछ बढ़ोतरी की है । पिछले साल यह 25 करोड़

8.00 P.M. 95 लाख रुपये था इस बार बढ़ा कर हमने 30 करोड़ किया है । हम आशा करके चलते हैं कि राजस्थान कैनाल का काम तेजी के साथ आगे बढ़ सकेगा लेकिन मुझे क्षमा करेंगे कि मैं अभी 15 दिन पहले राजस्थान केनाल पर गया था मैंने खुद जा कर जानकारी की थी पिछले तीन सालों में जिस तेजी के साथ काम चलना चाहिए था वह नहीं चला । हो सकता है सीमेंट की वजह से यह हुआ हो लेकिन ऐसे कामों के लिए सीमेंट वगैरह जुटाए जाते हैं । इस बात की व्यवस्था हम कर रहे हैं कि चाहे जो भी कारण रहा हो भाभड़ा जी के सुझाव को मान कर उन कारणों को दूर करेंगे और राजस्थान केनाल के निर्माण का कार्य जितनी जल्द हो सकेगा पूरा करने का प्रयास करेंगे ।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : 300 करोड़ रुपये खर्च करने हैं आप ध्यान में रखिए । आप तो 30 करोड़ कह रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह आंकड़े आप याद रखते हैं क्योंकि आपके पास और कहने को कुछ नहीं है । मैं आप को बताना चाहता हूं मैं आंकड़ों में नहीं पड़ता । रुपयों के वजह से काम को नहीं रोका जाएगा चाहे वह राजस्थान केनाल का सवाल हो या अकाल में राहत कार्यों का सवाल हो । श्री नत्थी सिंह जी ने कहा कि 7 करोड़ रुपये अकाल के लिए रखे गए हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि 7 करोड़ रुपये तो राजस्थान का ही हिस्सा है । जो बात उन्होंने कही वह अपनी जगह पर सही हो सकती है । 18 करोड़ 75 लाख रुपये के लिए जो सुझाव हमने दिया था उसको भारत सरकार ने ज्यों का त्यों मान लिया और आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के जमाने के अन्दर केवल पांच करोड़ रुपये खर्च किए हैं । अब इन दो महीनों के अन्दर पांच करोड़ रुपये हमने खर्च किए हैं । इस का मतलब यह है कि 10 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं । अब हम इस कुल राशि में से 10 करोड़ निकाल लें तो भी हमारे पास 8 करोड़ 75 लाख रुपये बाकी हैं । लेकिन जहां तक अकाल का ताल्लुक है, राहत कार्यों का सवाल है पैसों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । राजस्थान की सरकार जितना चाहे खर्च करे हम पूरी तरह से मदद करना चाहते हैं । हम जानते हैं कि अभी फूड फार वर्क प्रोग्राम जो चला था उसके अन्दर बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं ।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : ईरान से जो रुपया राजस्थान केनाल के लिए मिलने की बात है, विश्व बैंक से 50-60 करोड़ रुपया मिलना है उसके बारे में कुछ कहिये ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : वह मामला अभी चल रहा है । इसी प्रकार से श्रीमन्, उन्होंने जो अनाज के बदले काम की योजना की बात की हमने कहा कि उसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं । लेकिन मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूं मैं एक ही बात जानता हूं कि रेट बढ़ने की बात माननीय

सदस्यों ने अखबारों में पढ़ी होगी। प्रधान मंत्री जी अभी एक दो दिन पहले मध्य प्रदेश में गई थीं वहां पर इस सवाल को उठाया गया था। उन्होंने खुद कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य थोड़ा तसल्ली के साथ इंतजार करें तो यह फैसला जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि तीन किलो की बात आपने कही। यह तो राहत कार्यों में, सूखे के काम में जो चलता है उसमें है। पांच किलो की जो बात कही वह तो नार्मल फूड फार वर्क प्रोग्राम के अंदर चलता है। इन दोनों के अन्तर को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए मध्य प्रदेश में प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। हम आशा करके चलते हैं कि वह फैसला शीघ्र आपके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से लैंड रेवेन्यु की बात कही गई। जहां जहां सूखा पड़ा हुआ है, ओले पड़े हैं बाढ़ से नुक्सान हुआ है वहां पर कई जगहों पर यह सस्पेंड किया गया है। लैंड रेवेन्यु का फैसला अब सरकार ने किया है इसलिए इसको मैं दोहरा रहा हूं। जो शार्ट टर्म लोन हैं उनको मीडियम टर्म लोन कर दिया गया है और जो मीडियम टर्म लोन हैं उनको लांग टर्म कर दिया गया है। इससे कुछ राहत मिल जाएगी। ओले की बात जो की गई उसकी तरमीम हो कर अभी नहीं आई है, इसका तखमीना अभी नहीं बना है। जांच पड़ताल हो रही है। इसको शायद खतोनी कहते हैं, माननीय सदस्य वकील हैं और मेरे से ज्यादा जानते हैं तो वह जैसे ही खतोनी बन कर आ जाएगी, अन्दाजा जैसे लग जाएगा हम उस पर विचार करेंगे। माननीय सदस्य ने पंजाब के बजट पर भी फसल बीमा की योजना की बात की थी। श्रीमन, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी यह राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके होता है। तीन राज्यों में अभी यह काम चालू है लेकिन इसके अन्दर कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ आइटम्ज को लिया गया है। जैसे जैसे राज्य सरकारें स्वीकार करती जाती हैं केन्द्रीय सरकार तो चाहती है कि फसल का बीमा होना चाहिए। लेकिन किस फसल का बीमा होना चाहिए और किस का नहीं होना चाहिए, यह एक विस्तार का विषय है। जैसे कि मैंने निवेदन किया जैसे जैसे राज्य सरकार किसी आइटम को मंजूर कर लेती है उसका बीमा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार तो यह कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा आइटम्ज इसमें कवर हो जाएं।

श्री नत्थी सिंह : लेकिन जो ओले पड़े हैं वहां पर जो बात मुआवजे की हरियाणा सरकार करती है अब तो आपकी हर जगह सरकार है आप भी गरीबों को राहत दिलाइये। मुआवजा देने की बात कीजिए नहीं तो किसान भूखा मर जाएगा।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्य को शायद यह याद नहीं कि हरियाणा में भी हमारी सरकार है। हमारी सरकार जो अच्छा काम करती है...

श्री नत्थी सिंह : हरियाणा में देवीलाल की सरकार ने हमारी सरकार के समय में किया था आप भी राजस्थान में कर दें आपका गुण गायेंगे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपको शायद याद नहीं है वहां भी हमारी सरकार है। देवीलाल आपका कितने दिन... (*Interruptions*).

श्री नत्थी सिंह : वह गिर गई। बढ़िया काम किया। जितने दिन रहे उसको याद करेंगे कि तीन सौ रुपया मुआवजा दिया एकड़ पर।... *(Interruptions)*

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हम तो इससे भी अच्छा करना चाहते हैं, आप इन्तजार करें।

श्री नत्थी सिंह : सोच रहे हो या कुछ करोगे। दोगे कि नहीं... *(Interruptions)*. माननीय मन्त्री जी को पता है कि क्या हालत हो गयी है?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं माननीय सदस्य के कई सुझाव मान रहा हूं। मैं खुद मानता हूं कि पिछले दिनों के अन्दर किसानों को काफी परेशानी रही डीजल की रही, कैरोसीन की और बिजली की रही। लेकिन मैं आशा करके चलता हूं, माननीय सदस्य इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि जब से पिछली सरकार भंग की गयी है, हालांकि उसमें कुछ विलम्ब तो जरूर हुआ लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिजली के वितरण में, डीजल के वितरण में सुधार हुआ है और यह हो सकता है कि जितनी मात्रा चाहिए थी उतनी मात्रा में वह हम नहीं दे पाये हों लेकिन निश्चित रूप से हमने कोटे को बढ़ाया है। एक लाख किलो क्या उसको कहते हैं, भूल जाता हू आंकड़ा--तो उसको बढ़ाया है। अभी की बात है जब पिछली सरकार थी तब केवल 10 सौ लिटर डीजल रोजाना राजस्थान में मिलता था अब तो वह 30 के करीब मिल रहा है। श्रीमन्, आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूं कि अब पम्प सैट के साथ ट्रैक्टर को भी देना शुरू कर दिया है। हम जानते हैं कि हार्वेस्ट सीजन शुरू हो रहा है।... *(Interruptions)* हमको बताया गया था कि खतौनी की पूरी जांच नहीं हो पायी है... *(Interruptions)*. खतौनी की हो रही है... *(Interruptions)*

श्री नत्थी सिंह : जांच पड़ताल हो जायगी फिर दोगे?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : उसके बाद राजस्थान की सरकार विचार करेगी और राजस्थान की सरकार का सुझाव आयेगा तथा हम कुछ राहत दे सकते होंगे तो जरूर देंगे। राजस्थान की अन्य बातों के साथ ला एण्ड आर्डर की चर्चा भी माननीय सदस्यों ने की। श्रीमन्, इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि जैसे ही सरकार बदली है बड़े जोर के साथ कुछ एण्टी सोशियल एलीमेंट्स ने अपने करिश्मे दिखाये। मैं यह नहीं कहना चाहता था कि उसमें किस किस का हाथ था लेकिन यह बात सही है। लेकिन अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके क्राईम सिचुएशन कण्ट्रोल में आती जा रही है। सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि ये चोरियां, डकैतियां, राहजनी और मर्डर के केसेज बढ़े थे उनको न केवल कण्ट्रोल करे बल्कि कोशिश इस बात की है कि उनको पूरे तौर से, समूचे तौर पर समाप्त कर सकें। उसमें पुलिस के अधिकारियों का, कर्मचारियों का तत्व तो है ही परन्तु उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें दिन प्रतिदिन बहुत जोरों के साथ अपनी बात को कहना पड़ेगा। हम कई बार अपनी बात कहने में दब जाते हैं। मुझे क्षमा करेंगे, कई मामले ऐसे आ जाते हैं जहां कि हमें जोर से बोलना चाहिए पर नहीं बोलते हैं। कई बार तो पुलिस को सपोर्ट नहीं मिलता है, कई बार हम जाति पांति और धर्म के चक्कर में आ जाते हैं। यह बात मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं। इस बात की मैं आशा करके चलता हूं कि माननीय सदस्य जो सुझाव यहां पर देते हैं वे इस बात को ध्यान में रख कर देंगे कि जहां आवश्यकता हो वे अच्छी बात का समर्थन करेंगे। मैं समझता हूं कि सभी बातों की चर्चा, जो माननीय सदस्यों ने बातें कही थीं, उनके बारे में मैंने कर दीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया और आशा करता हूं कि उनका समर्थन हम को मिलेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Now, we

take up the Rajasthan Appropriation (Vote on Account) Bill, 1980. The question is:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Rajasthan for the services of a part of the financial year 1980-81, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill. There are no amendments.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGANNATH PAHADIA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Now, we take up the Rajasthan Appropriation Bill, 1980. The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Rajasthan for the services of the financial year 1979-80, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI JAGANNATH PAHADIA: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): The House stands adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at eleven minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 26th March, 1980.

GMGIPMRND—RS I—2O RS—2-6-80—570